

13/5/2022

पगावली पैरा हुई। अधिवक्ता वादी
उपस्थित, पगावली ~~विकल्प~~
~~विकल्प~~ में विकल्प उद्देश्य प्राप्त
हो चुका है इसलिए पगावली ने
अग्रिम पुनर्वादी पर कार्यवाही चाही
गई। पगावली से ~~उत्तर~~ (प्रतिक्रिया)
कार्यवाही की गई थी शेष ने
राजधानी विकल्प का। ~~उपस्थित~~
विकल्प पर कथन हुनी गई।
उपस्थित विकल्प ले पकड़कर

बखानवान

बनाम

मुकदमा नं.

ऑनलाईन नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

नम्बर व तारीख अलफाम जो हुकम की लागील में जारी हुए

सद्वत है। हुताधिक प्रायतन
 विमानत फाइनेल डिप्टी
 जारी है। आदेश से इजलास
 पुनास गार । फावली मेल
 सुमार हेड नम्बर ले कर
 है।





निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 132/2021

तारीख दायरा:- 04.10.2021

उनवान

1. मुकेश कुमार खींची पुत्र रामनारायण जाति खटीक।
2. गायत्री खींची पत्नि मुकेश कुमार खींची जाति खटीक निवासीगण सांगोद हाल गोपाल विहार कोटा।
3. बृजेश वसवाल पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी महावीर नगर विस्तार योजना कोटा।

-वादीगण

बनाम

1. रामावतार पुत्र नाथूलाल जाति खटीक।
2. रामावतार पुत्र रामगोपाल जाति बलाई निवासीगण सांगोद कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री बहादुर सिंह (वकील वादीगण)

दिनांक :- 16.03.2022

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादी)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख.न. 329 रकबा 2.72 है. वाके ग्राम सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से खातेदार हैं। उक्त आराजी में वादीगण कुल आराजी के 61/135 भाग अर्थात कुल रकबा 2.72 है. में से 1.22 है. पर काबिज काशत है जो आराजी के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 आराजी के मध्य भाग एवं प्रतिवादी सं. 1 आराजी के उत्तरी भाग में हिस्से अनुसार काबिज काशत हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अपनी काशत की सुविधा हेतु कृषि जोत का विभाजन कर रखा है तथा अपने-अपने हिस्से की उक्त विभाजन अनुसार मेडबन्दी कर रखी है जो मौके पर स्थित है।

राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कृषि भूमि से संबंधित कृषि विकास कार्य, ऋण लेने, विद्युत कनेक्शन आदि लेने बाबत संयुक्त खातेदारी की भूमि में सभी खातेदारों की सहमति आदि का प्रावधान होने एवं उक्त आराजी के खातेदार एक परिवार के नहीं होने से कृषि कार्य योजना सम्पन्न नहीं हो पा रही है जिसके लिए राजस्व रिकार्ड में बंटवारा करवाना आवश्यक हुआ है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से दिनांक 21.09.2021 को उक्त आराजी के रिकार्ड में बंटवारा करवाने हेतु तहसील कार्यालय सांगोद में उपस्थित होने बाबत कहा जिस पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया जिस पर वादीगण द्वारा वाद न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए प्रतिवादी सं. 3 को आदेशित किया जावे कि वो बाद जांच आराजी के खातेदारों के विभाजन रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर फाईनल डिक्री

पारित कर प्रतिवादी सं. 3 को राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार गिन नम्बर कायम करते हुए विभाजन अंकन किये जाने के आदेश पारित करें।
उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री लोकेश पोटर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री सुशील कुमार शर्मा द्वारा अण्डर टेकिंग दी गई परन्तु बाद में न तो वे स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए ना ही प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 राजस्थान सरकार प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। इसके बाद वादीगण अधिवक्ता ने इकबाली जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा आदि का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि -

माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 329 रकबा 2.72 है. आराजी में मौके पर काबिज काशत की स्थिति अनुसार विभाजन रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार सांगोद को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमीश्नर फीस 200 रूपये मुकर्रर की जाती है। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यु नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें। विवादित

आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहस्रपाठ)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद (बीटा)

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहस्रपाठ)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद (बीटा)